

सामान्य अर्थशास्त्र

व्यष्टिगत आर्थिक विश्लेषण



डॉ. देवा राम

वैकल्पिक एवं सामुदायिक उद्योगों की प्रमोदना
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(राष्ट्रीय विकास और उद्योग विकास विभाग)
नया दिल्ली



॥ राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी ॥



प्रस्तुत पुस्तक "सामान्य अर्थशास्त्र-व्यष्टिगत आर्थिक विश्लेषण" पाँच इकाइयों तथा सत्रह अध्यायों में विभक्त है जो कि सरल व सुगम्य भाषा में लिखी गई है। प्रथम इकाई अर्थशास्त्र तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय प्रस्तुत कर रही है तो द्वितीय इकाई उपभोक्ता के व्यवहार से सम्बन्धित विषयवस्तु उपयोगिता एवं मँग के नियम इत्यादि मामलों को चित्रों की सहायता से सुपाठ्य भाषा में व्याख्या करती है। इकाई तृतीय उत्पादक के व्यवहार अर्थात् उत्पादन व लागत सिद्धान्तों को उचित उदाहरणों व रेखा चित्रों से वर्णन करती है वहीं इकाई चतुर्थ बाजार के विभिन्न रूपों को विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास करती है। इकाई पंचम में वितरण के समस्त नियमों/सिद्धान्तों की व्याख्या की गई है जिसमें लाभ, व्याज, लगान, मजदूरी को सरलता से समझते हुए इनके वितरण सम्बन्धी सिद्धान्तों की व्याख्या की गई।

यह पुस्तक अर्थशास्त्र विषय का प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त करने वाले पाठकों, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

सामान्य अर्थशास्त्र

व्यष्टिगत आर्थिक विश्लेषण

(बी.ए. प्रथम वर्ष एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए)

लेखक

डॉ. देवा राम

सह आचार्य-अर्थशास्त्र

डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
निम्बाहेड़ा (राज.)



॥ राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी ॥
जयपुर

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की
विश्वविद्यालय-स्तरीय ग्रन्थ-निर्माण योजना के अन्तर्गत,
राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर द्वारा प्रकाशित।

प्रथम संस्करण : 2019
(प्रतियाँ 1100)

सामान्य अर्थशास्त्र : व्यक्तिगत आर्थिक विश्लेषण
ISBN 978-93-88776-10-3

मूल्य : 200.00 रुपये मात्र

© सर्वाधिकार प्रकाशक के अधीन

प्रकाशक :

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
प्लॉट नं. 1, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र
जयपुर- 302 004

दूरभाष : 0141-2711129, 2710341

Web-Site : www.rajhga.com.

लेजर कम्पोजिंग :

अकित प्रिन्टर्स, जयपुर

फोन : 9784924040

विषय-सूची

- इकाई-I : अर्थशास्त्र का परिचय**
- अध्याय : 1.** अर्थशास्त्र का अर्थ, परिभाषाएँ, विषय क्षेत्र एवं प्रकृति 1-19
 अर्थशास्त्र का इतिहास, अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाएँ, अर्थशास्त्र का क्षेत्र, विषयवस्तु एवं प्रकृति, अर्थशास्त्र-विज्ञान के रूप में, अर्थशास्त्र-कला के रूप में, अर्थशास्त्र-सकारात्मक (यथार्थ) अथवा आदर्शात्मक अध्ययन
- अध्याय : 2.** अर्थशास्त्र की अध्ययन पद्धतियाँ एवं साम्य 20-32
 अध्ययन पद्धतियाँ (Methodology), निगमन तथा आगमन कार्य विधि (पद्धतियाँ), स्वैतिक एवं प्रावैगिक विश्लेषण पद्धतियाँ
- अध्याय : 3.** अर्थशास्त्र की केन्द्रीय समस्याएँ एवं उत्पादन सम्भावना वक्र 33-39
 मूल आर्थिक समस्याएँ/अर्थशास्त्र की केन्द्रीय समस्याएँ, उत्पादन सम्भावना वक्र।
- इकाई-II : उपभोक्ता का व्यवहार**
- अध्याय : 4.** उपयोगिता विश्लेषण 40-60
 गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण या उपागम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, उपभोक्ता का सन्तुलन, क्रमवाचक उपयोगिता उपागम या दृष्टिकोण (विश्लेषण), उदासीनता वक्र व उदासीनता वक्रों की सहायता से उपभोक्ता का संतुलन।
- अध्याय : 5.** माँग का सिद्धान्त (Theory of Demand) 61-79
 माँग का अर्थ, माँग वक्र, माँग को प्रभावित करने वाले तत्व, माँग का नियम व प्रभाव (कीमत प्रभाव, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव), आय-उपभोग व एंजिल वक्र।
- अध्याय : 6.** माँग की लोच (Elasticity of Demand) 80-99
 माँग की लोच की अवधारणा, माँग की कीमत लोच, माँग की लोच की कोटियाँ, माँग की लोच का मापन, माँग की आय लोच, माँग की आडी लोच, पूर्ति लोच, उपभोक्ता की बचत।

(viii)

इकाई-III : उत्पादक का व्यवहार - उत्पादन सिद्धांत व लागत सिद्धांत

- अध्याय : 7. उत्पादन तथा उत्पादन फलन
(Production & Production Function) 100-138
उत्पादन तथा उत्पादन फलन, अल्पकालीन उत्पादन फलन - विविध अनुपातों के नियम, दीर्घकालीन उत्पादन फलन - समोत्पत्ति वक्र, पैमाने के प्रतिफल, उत्पादन की तीन अवस्थाएँ, साधन प्रतिस्थापन व इसकी दर, समलागत रेखा व साधनों का अनुकूलतम संयोग या न्यूनतम लागत संयोग, विस्तार पथ
- अध्याय : 8. लागत अवधारणा/लागत सिद्धांत 139-153
(Concept of Costs)
उत्पादन लागत, अल्पकालीन लागतें व लागत वक्र, लागतों में अन्तर्सम्बन्ध, दीर्घकालीन लागतें
- अध्याय : 9. आगम अवधारणा एवं आगम वक्र 154-163
(Concept of Revenue and Revenue Curves)
कुल आगम, औसत आगम व सीमांत आगम, औसत आगम, सीमांत आगम तथा लोच में संबंध।
- इकाई-IV : बाजार एवं बाजारों के प्रकार
- अध्याय : 10. बाजार के स्वरूप एवं पूर्ण प्रतियोगिता 164-177
बाजारों के विभिन्न रूप/वर्गीकरण, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार व पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत उद्योग व फर्म का सन्तुलन, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन सन्तुलन, ब्रेक-इवन अथवा शट-डाउन पॉइन्ट (उत्पादन बन्द करो का बिन्दु)
- अध्याय : 11. एकाधिकार (Monopoly) 178-191
एकाधिकार का अर्थ एवं परिभाषा, अल्पकाल एवं दीर्घकाल में एकाधिकारी फर्म का सन्तुलन, कीमत व उत्पादन का निर्धारण, कीमत विवेक की दशा में एकाधिकारी का सन्तुलन, एकाधिकारी शक्ति का मापन, करारोपण एवं सन्तुलन
- अध्याय : 12. अपूर्ण प्रतियोगिता-एकाधिकारत्मक प्रतियोगिता, अल्पाधिकार व अन्य बाजार 192-206
अपूर्ण प्रतियोगिता - द्वैयाधिकार, अल्पाधिकार, एकाधिकारत्मक प्रतियोगिता, एकाधिकारत्मक प्रतियोगिता में फर्म का सन्तुलन तथा कीमत व उत्पादन निर्धारण।

(ix)

इकाई-V : वितरण के सिद्धांत

- अध्याय : 13. वितरण का सिद्धांत-सीमांत उत्पादकता सिद्धांत 207-220
वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की व्याख्या, मान्यताएँ, आलोचनाएँ 221-234
- अध्याय : 14. मजदूरी निर्धारण के सिद्धांत 221-234
मजदूरी की अवधारणा, मजदूरी निर्धारण के सिद्धांत - मजदूरी का आधुनिक अथवा मॉग एवं पूर्ति का सिद्धांत, सामूहिक सौदेबाजी व मजदूरी निर्धारण 235-244
- अध्याय : 15. लगान (Rent) 235-244
लगान की अवधारणा व लगान के सिद्धान्त, रिकार्डो का लगान सिद्धांत - अन्तरीय या भेदात्मक लगान, दुर्लभ लगान, आभास (अर्द्ध) लगान (Quasi Rent) 245-253
- अध्याय : 16. लाभ एवं लाभ के सिद्धांत 245-253
(Profit and Theories of Profit)
लाभ की अवधारणा व सिद्धांत, लाभ का नवप्रवर्तनों का सिद्धांत या शुम्पीटर का लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत, हॉले का जोखिम सहन लाभ का सिद्धांत, नाइट का अनिश्चितता वहन का लाभ सिद्धांत
- अध्याय : 17. ब्याज के सिद्धांत (Theories of Interest) 254-270
ब्याज का अर्थ व परिभाषा, ब्याज के सिद्धांत-ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धान्त, कीन्स का ब्याज का तरलता पसन्दगी सिद्धांत, ब्याज का आधुनिक सिद्धांत: हिक्स व हेन्सन का IS-LM वक्र मॉडल, IS व LM वक्रों द्वारा ब्याज दर का निर्धारण, आधुनिक सिद्धान्त की समीक्षा।



डॉ. देवा राम

सह आचार्य-अर्थशास्त्र

डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, निम्बाहेड़ा (राज.)

शिक्षा—एम. ए.-अर्थशास्त्र 1998 में, पी.एच.डी.-अर्थशास्त्र
2002 में, अर्थशास्त्र विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय,
जोधपुर से की एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की परीक्षा नेट
व जेआरएफ जून 1998 में उत्तीर्ण की।

अध्यापक अनुभव—16 वर्षों से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में
राजस्थान महाविद्यालय शिक्षा के अन्तर्गत डॉ. भीमराव अम्बेडकर
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, निम्बाहेड़ा (राज.) में अध्यापन
का कार्य कर रहे हैं।

शोध/प्रकाशन/शोध परियोजना—2 पुस्तक एवं 16 शोध
पत्र प्रकाशित, 25 से अधिक सेमिनार/सम्मेलनों में भाग लिया एवं
पत्रवाचन किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्वीकृत 02
लघु शोध परियोजना पूर्ण की।

सदस्यता—भारतीय आर्थिक परिषद (आई. ई. ए.) राजस्थान
आर्थिक परिषद (आर. ई. ए.) भारतीय अर्थमिक्तिक समाज (टी
आई ई एस-द इण्डियन इकोनॉमेट्रिक सोसायटी) की लाइफटाइम
सदस्यता।

पता—169 विश्वकर्मा भवन, आदर्श कॉलोनी, निम्बाहेड़ा
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.), Email : dev.bhadrar@gmail.com

अकादमी द्वारा प्रकाशित वाणिज्य एवं अर्थशास्त्र विषयक पुस्तकें

1. विज्ञापन तकनीक एवं सिद्धान्त (सातवां सं.) नरेन्द्र सिंह यादव..... 305.00
ISBN 978-93-5131-280-2
2. संगठनात्मक व्यवहार (आठवां सं.)..... डॉ. पी.सी. जैन..... 395.00
ISBN 978-93-5131-271-0
3. विपणन अनुसंधान (च.सं.)..... डॉ. वी.कं. श्रीवास्ताव..... 255.00
ISBN 978-81-7137-683-4
4. विक्रय प्रबन्ध डॉ. एस.पी. माधुर..... 225.00
ISBN 978-81-7137-703-9
5. प्रबन्ध डॉ. एस.पी. माधुर..... 235.00
ISBN 978-81-7137-746-6
6. विज्ञापन प्रबन्ध (द्वि.सं.)..... नरेन्द्र सिंह यादव..... 90.00
ISBN 978-81-7137-973-6
7. वित्तीय प्रबन्ध प्रो. रेनु जटाना..... 255.00
ISBN 978-93-5131-160-7 डॉ. सागर सांवरेिया
8. व्यावसायिक अर्थशास्त्र..... डॉ. मुकेश माधुर,
डॉ. अरुणा गुप्ता..... 245.00
ISBN 978-93-5131-222-2
9. सामान्य अर्थशास्त्र..... डॉ. देवा राम..... 200.00
ISBN 978-93-88776-10-3

ISBN 978-93-88776-10-3



9 789388 776103

मूल्य : 200.00 रुपये मात्र

Website : www.rajhga.com

सामान्य अर्थशास्त्र

व्यक्तिगत आर्थिक विश्लेषण



डॉ. देवा राम

वैकल्पिक एवं तकनीकी प्रशासकीय आयोग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(आर्थिक शिक्षा और उन्नत शिक्षा विभाग)
नया दिल्ली



॥ राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी ॥

(ii)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की
विश्वविद्यालय-स्तरीय ग्रन्थ-निर्माण योजना के अन्तर्गत,
राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर द्वारा प्रकाशित

द्वितीय संस्करण : 2020
(प्रतियाँ 1100)

सामान्य अर्थशास्त्र : व्यक्तिगत आर्थिक विश्लेषण

ISBN 978-93-89260-90-8

मूल्य : 200.00 रुपये मात्र

© सर्वाधिकार प्रकाशक के अधीन

प्रकाशक :

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी

प्लॉट नं. 1, आलाना सांस्थानिक क्षेत्र

जयपुर- 302 004

दूरभाष : 2711129, 2710341

Website : www.rajhga.com.

मुद्रक :

श्री. हरिहर प्रिंटर्स

जयपुर



चाणक्य



राजस्थान की अर्थव्यवस्था

डॉ. देवा राम
सह आचार्य

राजस्थान की अर्थव्यवस्था (Economy of Rajasthan)

[राजस्थान के विश्वविद्यालयों में संचालित 'राजस्थान की अर्थव्यवस्था' के पाठ्यक्रम पर आधारित एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी पुस्तक]

लेखक

डॉ. देवा राम

सह-आचार्य (अर्थशास्त्र)

डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
निम्बाहेड़ा (राज.)

चाणक्य प्रकाशन

जयपुर



अनुक्रमणिका

क्र.सं.		पृष्ठ सं.
अध्याय 1	राजस्थान : एक परिचय	1
अध्याय 2	राजस्थान की अर्थव्यवस्था का वृहद परिदृश्य एवं भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थान पृष्ठभूमि, भारतीय, अर्थव्यवस्था में स्थान— जनसांख्यिकी, क्षेत्र, कृषि, आधारभूत संरचना, उद्योग व वित्त तथा अन्य घटकों के आधार पर।	3
अध्याय 3	राजस्थान में प्राकृतिक संसाधन: भूमि, वन, जल, खनिज सम्पदा राज्य में भूमि व भू-उपयोग, मिट्टियाँ, जलवायु, राज्य में वन क्षेत्र व महत्व, राज्य में जल संसाधन—सतही जल व भूमिगत जल, राज्य में खनिज संसाधन—मण्डार क्षेत्र व अर्थव्यवस्था में योगदान।	14
अध्याय 4	राजस्थान की जनसांख्यिकी की विस्तृत विशेषताएँ राज्य की जनसंख्या का आकार, वृद्धि दर, घनत्व, लिंगानुपात, क्षेत्रीय एवं व्यवसायिक वितरण, राज्य में साक्षरता व मानव संसाधन विकास सूचक, जनसंख्या वृद्धि के कारण व नियंत्रण के उपाय।	32
अध्याय 5	राज्य घरेलू उत्पाद एवं इसकी प्रवृत्तियाँ राज्य घरेलू उत्पाद के विभिन्न घटक, अखिल भारतीय स्तर पर तुलना एवं राज्य घरेलू आय का क्षेत्रवार संयोजन व वितरण की प्रवृत्तियाँ	49
अध्याय 6	राजस्थान में कृषि परिदृश्य, कृषिगत विकास, विपणन, वित्त एवं भू-सुधार राज्य में कृषि हेतु भू-उपयोग व कर्बवशील जोते, फसल प्रारूप व प्रमुख फसलें, कृषिगत उत्पादन व उत्पादकता, कृषिगत विकास—समस्याएँ व समाधान, कृषिगत विपणन, वित्त व फसल बीमा, राजस्थान में भूमि सुधार।	61
अध्याय 7	राजस्थान में पशुधन: पशुपालन और डेयरी विकास राज्य में पशुधन सम्पदा का महत्व, पशुधन संख्या व नस्लें, पशुपालन की समस्याएँ एवं पशुपालन प्रोन्नति के लिए सरकारी प्रयास। राजस्थान में डेयरी विकास।	81

अध्याय 8	राजस्थान में आधारभूत संरचना (अवसंरचना) : ऊर्जा तथा परिवहन राजस्थान में ऊर्जा के स्रोत तथा विद्युत प्रस्थापन क्षमता-राष्ट्रीय, अधिकांश, जलवीय, पवन, सौर व बायोमास ऊर्जा संसाधन। राज्य में परिवहन ढाँचा-सड़क परिवहन सुविधाएँ व समस्वाह, रेल तथा वायु परिवहन सेवाएँ।	92	अध्याय 13	राजस्थान में पर्यटन विकास राज्य में प्रमुख पर्यटन स्थल/क्षेत्र/मठ/मठ/संस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यटन का राज्य की अर्थव्यवस्था में स्वल्प पर्यटन विकास के प्रयास व उपलब्धियाँ। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (आरटीडीसी) पर्यटन की संरचनाएँ व सुविधाएँ।	153
अध्याय 9	राजस्थान में बहुददेशीय नदी घाटी एवं सिंचाई परियोजनाएँ राज्य में बहुददेशीय परियोजनाएँ (माखड़ा-नांगल, म्यास, कम्बल, बाही-बजाज परियोजनाएँ), अन्य सिंचाई परियोजनाएँ (बृहद्-इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, राष्ट्रीय गांधी सिद्धमुख नहर, नर्मदा नहर, बीसलपुर, जाखन, परवन, जवाई, वजुना जल, मेजा बांध व पूर्वी नहर, मधवल-मनोहर धान, गांगरिन, पीपलाद, मरडदा, तकली एवं अन्य महत्वपूर्ण व लघु सिंचाई परियोजनाएँ)।	107	अध्याय 14	राजस्थान में निर्धनता की समस्या एवं निवारण के उपाय निर्धनता की अवधारणा, राज्य में निर्धनता के अंकड़े व कारण, राज्य में राष्ट्रीय उन्मूलन के प्रयास व निर्धनता निवारण तथा रोजगार सृजन के कार्यक्रम (IRDP, TRYSEM, DWACARA, SITRA, MWS, GKY, SGSY, NREP, RLEGP, JRY (JGSY), NRY, SGRY, DPIF, MPOWER, MNREGA)	167
अध्याय 10	राजस्थान में उद्योग एवं औद्योगिक विकास राज्य में उद्योग व उनका वर्गीकरण-कच्चे भात की उपलब्धता आधारित उद्योग, निर्यात आधारित उद्योग, निर्यात आधारित उद्योग (एल्वि व लघु उद्योग क्षेत्र आधारित-सूती वस्त्र, चीनी, धातु-तेल, दुग्ध उत्पाद उद्योग, खनिज आधारित-सीमेंट, काच, अन्नक, पत्थर-नगीना-मेटल-तरल आधारित उद्योग, रसायन आधारित-नमक, उर्वरकउद्योग एवं अन्य इंजीनियरिंग-इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक्स आदि उद्योग)। राज्य में छोटे व मध्यम पैमाने के उद्योग।	118	अध्याय 15	राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या राज्य में बेरोजगारी के प्रकार, अंकड़े तथा कारण, बेरोजगारी दूर करने के उपाय व व्यास तथिति के सुझाव।	181
अध्याय 11	राजस्थान में औद्योगिक विकास एवं वित्त के निगम व उद्यमिता विकास राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व निर्यात निगम लिमिटेड (राजको), विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी), राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (राजसीको), ग्रामीण मंत्र-कृषि विकास एजेंसी (रुडा), राज्य में उद्यमिता विकास तथा प्रोत्साहन विकास क्षेत्र।	133	अध्याय 16	राजस्थान में अकाल व सूखा (राज्य की विशेष समस्याएँ - अकाल व सूखा) राज्य में अकाल व सूखे की व्यापकता व कारण, राज्य में अकाल व सूखे के प्रतिबन्ध प्रभाव को कम करने के अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाय एवं नीतियाँ।	187
अध्याय 12	राज्य में बुनियादी सामाजिक सेवाएँ (सर्विस सेक्टर) : शिक्षा एवं स्वास्थ्य राज्य में शिक्षा सुविधाएँ, शैक्षिक स्तर व चुनौतियाँ (स्कूली, उच्च व तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान), राज्य में शिक्षितता एवं स्वास्थ्य सुविधाएँ, स्वास्थ्य संकेतक व सरकारी योजनाएँ।	145	अध्याय 17	राजस्थान में विविध क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम-सूखा समाहित क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP), मरु विकास कार्यक्रम (DDP), अल्पवनी विकास कार्यक्रम (ADP), जल मेवास-डीग-कच्छ-सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जनजाति विकास कार्यक्रम-जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम (TADP), व जनजाति उद्योग (TSP), माछा, ग्रामीण जनजाति व शिक्षित जनजाति विकास कार्यक्रम आदि।	194

राज्य के बजट 2022-23 व 2021-22 के राजकाशीय संकेतक, राज्य बजट की प्रवृत्तियाँ

राज्य में आर्थिक नियोजन के दौरान योजनाबद्ध व मददार व्यय आपंटन के साथ चर्चें तथा उपलब्धियों की चर्चा। राज्य के आर्थिक विकास की बाधाएँ व विकास हेतु सुझाव।

□□□

202

208

अध्याय 1

राजस्थान : एक परिचय

राजस्थान जमान में भारत के 29 राज्यों और 8 केन्द्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर (3,42,239.74 किमी²) है जो कि भारत के कुल भू-भाग का 10.41 प्रतिशत हिस्सा है।

राजस्थान का यह वर्तमान स्वरूप नवम्बर 1956 में अस्तित्व में आया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अजमेर-मेरवाड़ा प्रदेश ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत सीमा जुड़ा था जबकि राजस्थान का अन्य इलाका अलग-अलग 19 देशी रियासतों और 3 ठिकानों में विभक्त था। आजादी के बाद अजमेर-मेरवाड़ा को ब्रिटिश शासन का अंग होने से भारत का हिस्सा बन गया लेकिन रियासतों और ठिकानों को एकीकृत करने के लिए 8 वर्ष से भी अधिक का लम्बा समय लगा। राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण मार्च 1948 में आरम्भ हुआ जो सातवें चरण के साथ नवम्बर 1956 में समाप्त हुआ, यह सन्ततय 8 वर्ष व साढ़े सात महीने की रही।

राजस्थान भारत के उत्तर-पश्चिम भाग में 23° 30' से 30° 12' उत्तरी अक्षांश और 69° 30' से 78° 17' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है जिसका आकार लगभग एक घण्टा जैसा है। उत्तर से दक्षिण राज्य की लम्बाई 628 किमी. है तो पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869 किमी. है। 1070 किमी की लम्बी पश्चिमी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगी है जबकि उत्तर से पूर्व होते हुए दक्षिण तक चलेनी सीमा जो 5860 किमी. है क्रमशः पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, और गुजरात से लगी हुई है।

थार मरुस्थल (ग्रेट थ्रिडगन टेजर्ट) का 85 प्रतिशत भाग भारत में विस्तारित है जिसमें से कुल का 61.11 प्रतिशत भाग अकेले राजस्थान में है जो मुख्यतः 12 जिलों तथा जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बुध, सीकर, सुन्सुई, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर में फैला हुआ है। इस प्रकार राज्य का लगभग दो-तिहाई भाग (लगभग 1,89,208 वर्ग किमी) रेगिस्तानी क्षेत्र है जो कि राजस्थान का परिवर्धोत्तर इलाका है। राज्य के भाग से अरावली पर्वतमाला गुजरती है जो दिल्ली के पास से आरम्भ होकर गुजरात राज्य तक जाती है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊँची चोटी मुल्शिहार राजस्थान के सिरोही जिले के माउन्ट आबू में स्थित है जिसकी ऊँचाई 1772 मीटर है जबकि दूसरी ऊँची चोटी रोह, सिरोही (1587 मीटर ऊँचाई), तीसरी ऊँची चोटी जयरा (1431 मीटर ऊँचाई) चौथी अजमेर, सिरोही (1380 मीटर, ऊँचाई) है। इनके बाद क्रमशः आबू पर्वत (1295 मीटर), कुमलगढ़-राजसमर (1224 मीटर), जोलिया दूंगर-उदयपुर (1186 मीटर), धौनिया-सिरोही (1183 मीटर), रघुनाथगढ़-सीकर (1055 मीटर), सज्जन्गढ़-उदयपुर (830 मीटर), तारागढ़-अजमेर (873 मीटर) प्रसिद्ध चोटियाँ हैं। पर्वतमाला के दो प्रमुख दर्रे-देसुही दर्रा व हाथी दर्रा हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली मुख्य नदियाँ - बनास, नूनी, माही, बाणगंगा, कोठारी, खारी, जोजरी एवं बेबन हैं। अजमेर, पाली, सिरोही, गिरादगढ़, पदच्छुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों में पर्वतमाला विस्तारित है।



डॉ. देवा राम

सह आचार्य-अर्थशास्त्र

डॉ. भीमराव अम्बेकर राजकीय ज्ञानकोश महाविद्यालय, निम्बाहेडा,
जिला - बितीडगढ़ (राज.)

शिक्षा :

- एम. ए. अर्थशास्त्र (1998) एचम् पीएच.डी. (2002), अर्थशास्त्र विभाग,
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर (राज.)
- NET एचम् JRF (जून 1998) - यू.जी.सी.

अध्यापन :

- कॉलेज शिक्षा सेवा राजस्थान के अन्तर्गत 20 वर्षों से अर्थशास्त्र विषय
का अध्यापन ।

कृतियाँ/प्रकाशन/शोध :

- 2 सन्दर्भ पुस्तकें प्रकाशित,
- 1 पाठ्यपुस्तक (सामान्य अर्थशास्त्र : व्यक्तिगत आर्थिक विश्लेषण)
राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी जयपुर से प्रकाशित
- 15 से अधिक शोध पत्र व लेख प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं, संपादित
पुस्तकों में प्रकाशित ।
- 2 शोध प्रोजेक्ट (यू.जी.सी. द्वारा प्रायोजित) कार्य पूर्ण
- 20 से अधिक राष्ट्रीय सेमिनार में सहभागिता

शोध निर्देशन:

- मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से रिसर्च सुपरवाइजर के रूप में
पंजीकृत एचम् 07 रिसर्च स्कौलर आर्बिटल

सदस्यता/सम्मान:

- भारतीय आर्थिक परिषद (IEA),
- राजस्थान आर्थिक परिषद (REA),
- भारतीय अर्थवित्तीय सोसायटी (TIES) सदस्यता एचम्
- राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी जयपुर द्वारा लेखक सम्मान ।



चाणक्य प्रकाशन
जयपुर



TRANSFORMING INDIA 2030 :
A Roadmap for Sustainable Development Goals



Edited by : Dr. Dev Karan

TRANSFORMING INDIA 2030 :

A Roadmap for Sustainable Development Goals

Edited by :

Dr. Dev Karan

Assistant Professor

Department of Economics,

Jai Narain Vyas University, Jodhpur (Rajasthan)

Publication :

**USHA PUBLICATION HOUSE
JODHPUR**

INDEX

1. A Study on Achievement of Sustainable Development Goals from a Gender Equality Perspective - *Pradeep Kumar Panda* 1
2. NPAs in Banks Affecting the Development of India - *Neha Paliwal* 22
3. Higher Education in India & Skill Development : Catalysts of Employability in India - *Khushboo Niyarta* 37
4. India's Health System : Way Forward - *Bala Devi* 47
5. Demonetization of India Currency : An Elementary Drag towards Digital Economy - *Megha Jain & Abhikrati Shukla* 57
6. Assessing The Status of Interstate Financial Inclusion Process In India - *Deepa Soni* 67
7. Carbon Credit-Solution Step Towards Global Warming - *Peeyush Bangur & Abhikrati Shukla* 76
8. Gender Disparties in Labour Market : Duncan Dissimilarity Approach - *Laxman Lal Salvi* 89
9. Make in India : A Big Push to Manufacturing Sector - *Parvez Ali* 101
10. Growth with Digital Platform in Perspective of India and Rajasthan - *Ashish Kumar* 112
11. Achieving the Sustainable Development Goals 2030 with Special Reference to Agriculture from Indian Perspective - *Aruna Kumari* 119
12. Green Accounting : Concept and Importance - *Mangu Ram* 126
13. MGNREGA - A Prospect of Achieving Sustainable Development Goals through Poverty Reduction - *Rekha* 133
14. Stress Management Practicies For Employees : An Overview - *Ashok Kumar* 142
15. Climate Change And Sustainable Development - *Vrinda Ojha* 150
16. Access To Education : A Case Study of a Village - *Deva Ram* 158
17. Urbanization and Environment : Issues and Challenges - *Ekta Khator* 167
18. An Overview of Laws for Environmental Protection in Context of Sustainable Development - *Kuchta Ram* 175

Access To Education: A Case Study of A Village

Dr. Deva Ram

*Associate Professor, Dept. of Economics,
Dr. Bhimrao Ambedkar Govt. P G College,
NIMBAHERA (Dist. Chittaurgarh), Rajasthan*

Introduction

Human capital is the most important factor in economic growth, so human resource development is the prime goal of the modern world. Education, health and nutrition are the basic means for human resource development. The role of education in raising the consciousness is widely acknowledged in the contemporary world. And also in this new era most of the occupations require particular type of skill, that can be gain through education. Besides, education not only helps in getting good job but also means to attain high social status. It gives platform to individuals to involve in development process through imparting of information, knowledge and skills. Thus, education is the backbone for overall development of every society or nation and even whole world. The role of education in facilitating social and economic progress is well accepted. So that UNDP has included Inclusive and Quality Education as one of the most important goals for overall sustainable development.

According to Human Development Report (UNDP, 1993) literacy is a person's first step in learning and knowledge building and as a result literacy indicators are essential for any measurement of human development. Correspondingly, the literacy is one of the most significant indicators of the human development. This is an important component, out of three components, of Human Development Index (HDI), which is single composite index of human development of every country and has been publishing by United Nations Development Programme (UNDP) since 1990 as Human Development Report (HDR). Thus, literacy and basic education build fundamental structure for development of the country while higher education is recognized as a critical factor in inclusive and faster growth. Since the independence, government has been made many efforts to raise the level of literacy and education through various schemes, provisions and programmes. Likewise, National Literacy Mission (NLM), Total Literacy Campaign (TLC), Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), Operation Black-Board, National Policy Education (NPE), and now, Right of Children to Free & Compulsory Education (RTE) Act etc. Due to launching various schemes/programmes by

DISCLAIMER

The authors are solely responsible for the contents of the papers compiled in this volume.. The publisher or editors do not take any responsibility for the same in any manner. Errors if any, are purely unintentional and readers are requested to communicate such errors to the editors or publisher to avoid discrepancies in futurs.

Year of Publication - 2019

ISBN -978-81-921245-0-6

No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means without prior permission from the Editors.

© Editors

Publisher:

NATURAL GROWTH BOOKS

Jodhpur (Rajasthan)

Published in India

Feb. 2019

Published by Natural Growth Books, Jodhpur. Desigend & Printed
by Vijayant Vyas, Computer Craft, Johpur. Mobile 9314342165

(ii)

ISBN 978-81-921245-0-6



Rs. 400/-

Natural Growth Books
JODHPUR



डॉ. एम. आर. सिंगारिया



डॉ. हरीश कुमार

राष्ट्र निर्माण में डॉ. भीमराव
अम्बेडकर का योगदान



डॉ. एम. आर. सिंगारिया
डॉ. हरीश कुमार

● पदस्थापन : सहआचार्य एवं विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, स.घ. राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर (राजस्थान)

● आजीवन सदस्यता : 1. Indian Economic Association (IEA), 2. The Indian Econometric Society (TIES), 3. Indian Association for the Study of Population (IASP), 4. Rajasthan Economic Association (REA) ● शोध-क्षेत्र : आर्थिक विकास Economic Development, 2. Demographic Studies, 3. Econometric Analysis, 4. Macro Economics ● प्रकाशित पुस्तकें : 1. Population Growth and Economic Development in Rajasthan-An Econometric Analysis ● सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्पादक मण्डल : 1. Journal of Finance and Economics (JFE), 2. International Journal of Econometrics and Financial Management (IFEFM), 3. Growth (Asian online Journals.com) ● शोध आलेख : चालीस से अधिक शोध पत्र राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित।

सम्पर्क :

76, 'मातृ-कृपा' सेट सांवरिया कॉलोनी,
जालिया रोड, ब्यावर
Mobile : 9414496236
Mail ID : mr.singariya@gmail.com

● पदस्थापन : सहआचार्य, हिन्दी-विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जैतारण (पाली) राजस्थान ● शोध-क्षेत्र : अज्ञात एवं अल्पज्ञात सन्तों की वाणी, पाण्डुलिपियों पर शोधपरक अध्ययन ● प्रकाशन : 1. रामसनेही सम्प्रदाय : परम्परा एवं मूल्यांकन, 2. रामसनेही सन्त राधोदासजी : जीवन एवं दर्शन ● प्रकाशाधीन : 1. सन्त नामदेव, 2. भारतीय साहित्य एवं संस्कृति के विविध आयाम (सम्पादन) ● शोध आलेख : 30 से अधिक शोध-पत्र राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित ● शोधपरक अध्ययन हेतु सम्मानित : 1. भारतीय दलित साहित्य अकादमी, दिल्ली, 2. अखिल भारतीय रामसनेही सम्प्रदायाचार्य पीठ-रामधाम खेड़ापा, 3. अंतर्राष्ट्रीय श्रीरामसनेही-सम्प्रदाय (शाहपुरा), 4. अखिल भारतीय राजभाषा हिन्दी सेवी सम्मान पुरस्कार

सम्पर्क :

42, 'रुक्मिणी मंगल', महावीर कॉलोनी,
जालिया रोड, ब्यावर-305901 (अजमेर)
Mobile : 8432279323
Mail ID : hkumar171974@gmail.com



राष्ट्र निर्माण में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का योगदान



डॉ. एम. आर. सिंगारिया
डॉ. हरीश कुमार



प्रकाशक :
रायल पब्लिकेशन

प्रकाशक एवं वितरक

18, शक्ति कॉलोनी, गली नं. 2

लोको शेड रोड, रातानाडा,

जोधपुर-342 011 (राजस्थान)

Mobile : 094142-72591

E-mail : rroyalpublication@gmail.com

© सम्पादक

प्रथम संस्करण : 2021

मूल्य : ₹ 500.00

ISBN : 978-81-949377-3-9

मुद्रक : भारत प्रिण्टर्स (प्रेस), जोधपुर

लेज़र टाइपसेटिंग : रोहन कम्प्यूटर, जोधपुर

Rastra Nirmaan Mai Dr. Bhimrao

Ambedkar Ka Yogdaan

Editor : Dr. M.R. Singariya

Co-Editor : Dr. Harish Kumar

Royal Publication, Jodhpur

First Edition : 2021 • ₹ 500.00

सम्पादकीय

बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर का व्यक्तित्व बहुआयामी था। उनका सम्पूर्ण जीवन राष्ट्र और मानवता को समर्पित था। वे विपुल प्रतिभा के धनी, परिश्रमी अध्येता थे। सन् 1915 में उन्होंने कोलम्बिया विश्वविद्यालय से एम.ए. अर्थशास्त्र की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1921 में 'लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स' से 'डॉक्टरेट' की डिग्री हासिल की तथा 1922 में इंग्लैण्ड के ही 'ग्रेज इन' से 'बैरिस्टर एट लॉज' डिग्री उत्तीर्ण की, 1923 में अर्थशास्त्र में 'डॉक्टर ऑफ साइंस' की डिग्री प्राप्त की। बाबा साहब को शिक्षा प्राप्त करने की असीम जिज्ञासा थी इसी के चलते वे जीवन भर अध्ययन करते रहे। उनको 'डॉक्टरेट' की तीसरी और चौथी उपाधि क्रमशः कोलम्बिया विश्वविद्यालय से एल.एल.बी. (1952) तथा डी.लिट्. की डिग्री (1953) में उस्मानिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई।

बाबा साहब की बहुमुखी जीवन-साधना एवं लेखन ने एक पूरे और विशाल युग को प्रभावित किया। वे अनेक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले विद्वान थे। अंग्रेजी भाषा में उनको विशेष दक्षता हासिल थी, अतः उन्होंने अधिकांश लेखन इसी भाषा में किया। अगाध विद्वता में सहजता का मणिकांचन योग उन्हें असामान्य महामानव के रूप में प्रतिष्ठित करता है। उनके द्वारा लिखित पुस्तक 'रुपये की समस्या : इसका मूल्य एवं समाधान' में उन्होंने रुपये के मूल्य में गिरावट के कारण भारत की आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या की। उनका मानना था कि औद्योगिकरण द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना उनके द्वारा हिल्टन यंग कमीशन पर दिए गए विचार से हुई तथा भारत के वित्त आयोग के गठन में भी बाबा साहब ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

बाबा साहब का मानना था कि राजनैतिक राजसत्ता के बिना आर्थिक एवं सामाजिक राजसत्ता अधूरी है। उन्हें संविधान का मुख्य शिल्पी कहा जाता है। यह

4 • राष्ट्र निर्माण में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का योगदान

उनके कठिन परिश्रम एवं लगन का ही प्रतिफल था कि उन्होंने सभी वर्गों, सभी वर्णों, विभिन्न सम्प्रदायों एवं भौगोलिक परिस्थितियों में निवास करने वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए एक समान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया। जिसमें नागरिकों को स्वतन्त्रता, समानता एवं सुरक्षा प्रदान की गई। इसमें धर्म की आजादी, छुआछूत और भेदभाव के सभी रूपों को समाप्त करना भी सम्मिलित है। बाबा साहब महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के प्रबल समर्थक थे।

बाबा साहब ने अपने जीवन काल में अनेक शोध-पत्रों, पुस्तकों का लेखन, समाचार पत्रों का सम्पादन किया। उनका लेखन एक विशिष्ट सामाजिक दृष्टिकोण तथा असामान्य विद्वता के लिए जाना जाता है। उनके राष्ट्र निर्माण की अवधारणा, उदारता, समानता तथा सामुदायिकता पर आधारित थी। उन्होंने सदैव मानव अधिकारों के संरक्षण की वकालत की। हम चाहते हैं कि एक नई सोच के साथ उनके राष्ट्र एवं सामाजिक अवदान पर विस्तृत एवं व्यापक रूप से चिन्तन-मनन हो। इस पुस्तक के कुल 25 अध्यायों में बाबा साहब को इसी रूप में समझने का प्रयास विद्वान लेखकों, शोधार्थियों द्वारा किया गया है।

बाबा साहब के व्यक्तित्व एवं चिन्तन को पुस्तक रूप में सम्पादित करने की प्रेरणा हमें डॉ. जी.एस. चौहान (संयुक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली), प्रो. शक्ति कुमार (चैयरपर्सन-सी.ई.एस.पी., जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली), श्री जय नारायण शेर (आई.पी.एस.-डी.आई.जी. पुलिस अपराध शाखा, राजस्थान), प्रो. वी.एस. पंवार (सेवानिवृत्त प्राचार्य) एवं डॉ. अरुणा गुप्ता (प्राचार्य, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर) से मिलती रही। हम इनके द्वारा प्रतिपल सहयोग एवं प्रोत्साहन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। पुस्तक प्रकाशन में श्री सूर्यप्रकाश भार्गव (रॉयल पब्लिकेशन, जोधपुर) के सहयोग के लिए भी आभार।

अन्ततः जिस उद्देश्य को लेकर यह पुस्तक पाठकों के समक्ष प्रस्तुत की गई है, उसमें हम यत्किंचित भी सफल होते हैं तो अपने श्रम को सार्थक समझेंगे।

डॉ. एम. आर. सिंगारिया
डॉ. हरीश कुमार

अनुक्रमणिका

• सम्पादकीय	9
1. सामाजिक न्याय के सूत्रधार : डॉ. भीमराव अम्बेडकर —डॉ. प्रेमलता परसोया	9
2. अर्थशास्त्र एवं आर्थिक विकास के क्षेत्र में डॉ. अंबेडकर का योगदान —डॉ. देवा राम	25
3. हिन्दी साहित्य में दलित चेतना और डॉ. भीमराव अम्बेडकर —प्रतिमा खटुमरा	35
4. जल संसाधन संवर्धन एवं प्रबन्धन में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का योगदान —डॉ. श्रीमती रजनी वरुण	43
5. बहुआयामी व्यक्तित्व : डॉ. भीमराव अम्बेडकर —डॉ. सीमा शर्मा	48
6. समकालीन परिदृश्य में अंबेडकर के आर्थिक चिन्तन की प्रासंगिकता —धीरज कुमार पारीक	53
7. अम्बेडकर का सामाजिक दर्शन —डॉ. पूजा वरुण	61
8. महिला सशक्तिकरण एवं बाबा साहेब अम्बेडकर का योगदान —श्रीमती संगीता पांचाल	68
9. डॉ. बी.आर. अंबेडकर की महिला सशक्तिकरण में भूमिका —सुमन देवी शर्मा	75
10. डॉ. भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक न्याय सम्बन्धी विचार —डॉ. आशीष कुमार	88
11. बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर : एक युग प्रवर्तक —डॉ. राकेश वर्मा	100

अर्थशास्त्र एवं आर्थिक विकास के क्षेत्र में डॉ. अंबेडकर का योगदान

✍ डॉ. देवा राम

सह-आचार्य अर्थशास्त्र, डॉ. भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय, निम्बाहेड़ा, राजस्थान

परिचय

14 अप्रैल 1891 को 14वीं संतान के रूप में मध्य भारत के महू छावनी क्षेत्र में तत्कालीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की सेना के सूबेदार रामजी सकपाल और भीमा बाई के घर एक महान शख्सियत ने जन्म लिया जिन्हें हम बाबासाहेब डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर के नाम से जानते हैं। बचपन से ही विलक्षण बुद्धि के धनी डॉ. अंबेडकर एक प्रसिद्ध भारतीय विधिवेत्ता, राजनेता, मानव शास्त्री, दार्शनिक, इतिहासविद और प्रभावशाली वक्ता के साथ ही साथ एक अच्छे अर्थशास्त्री भी थे। न केवल उन्होंने अपने आरंभिक काल में अर्थशास्त्र का अध्ययन-अध्यापन ही किया वरन् बाद के वर्षों में अपने आर्थिक विचारों और मतों को भारतीय आर्थिक विकास में भी अपनाया तथा संविधान निर्माण में भी इसकी झलक देखी जा सकती है। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन भी डॉ. अंबेडकर को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अपना पिता मानते हैं (अंबेडकर इज माय फादर इन इकोनॉमिक्स)। एस. अम्बिराजन कहते हैं कि "यह अर्थशास्त्र प्रोफेशन के लिए दुर्भाग्य की बात रही कि डॉ. अंबेडकर ने अर्थशास्त्र के प्रोफेशन को छोड़कर विधि और राजनीति को चुनने का निर्णय लिया" लेकिन मेरा मानना है कि डॉ. अंबेडकर ने भले ही अर्थशास्त्र में अपने करियर को आगे बढ़ाने के बजाय विधि और राजनीति के क्षेत्र को अपनाया हो परन्तु उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में राष्ट्र के आर्थिक विकास और समाज के विकास में अपने आर्थिक अनुभवों को प्रायोगिक रूप प्रदान किया तथा विश्व में मानवता को स्थापित करने के लिए आर्थिक आधारों को स्तम्भ बनाया। प्रस्तुत आलेख अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बाबासाहेब अंबेडकर के योगदान को समझने

CERTIFICATE OF PUBLICATION
Archers & Elevators Publishing House

THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO

Dr. DEVA RAM

For publishing his/her paper in a Peer-Reviewed Edited Book



TITLE: INDIAN BANKING CRISIS IS IMPEDING ECONOMIC GROWTH

BOOK: Emerging Trends in Banking & Finance ISBN: 978-93-90996-49-0

7/08/2021

DATE


S. Mahalingam
Director - AEPH

EMERGING TRENDS IN BANKING & FINANCE

Sruthi.S.

Dr.Harbans Lal Sharma

Dr.P.Rengarajan

Dr.S.Durga

Dr.Harshada Aurangabadkar



Emerging Trends in Banking & Finance

Sruthi.S
Dr.Harbans Lal Sharma
Dr.P.Rengarajan
Dr.S.Durga
Dr.Harshada Aurangabadkar

Archers & Elevators Publishing House
Bangalore - 560 090 India.

ARCHERS & ELEVATORS PUBLISHING HOUSE

No.54, MM Layout,

Hesaragatta Main Road,

Bangalore -560090

Mob: + 91 9164362263

E-mail: archerselevators@gmail.com

Website: www.aeph.in

Emerging Trends in Banking & Finance

© Archers and Elevators Publishing House

First Edition 2021

ISBN: 978-93-90996-49-0

Price: ~~Rs.~~850/-

All rights reserved. This book or parts therefore, may not be reproduced in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or an information storage and retrieved system now known or to be invented, without written permission from copyright owners.

PRINTED IN INDIA

A & E printers, Bangalore-90.

CONTENTS

S.NO	TITLE OF THE PAPER	PAGE NO
1	ROLE OF INDIAN BANKING SECTOR IN PROMOTING FINANCIAL INTERMEDIATION ARCHANA BANHARDE, Dr. VINOD K.R., PADMINIUSHINI & VINEET BHATNAGAR	1
2	ARIMA MODELING USING E-views SOFTWARE DEBAPAN MOHANTY, SUTRITHI CHANDRASEKAR, Dr. YASIN SHEESH	8
3	CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: A CONCEPTUAL FRAMEWORK Dr. HIMANSHU MATHUR	17
4	IMPACT OF COVID-19 ON BANCASSURANCE IN INDIA Dr. NAZIA SULTANA, K.SRIDHARSHILA	22
5	EMERGING TRENDS IN BANKING INDUSTRY -AN INSIGHT FROM ITS OPPORTUNITIES & CHALLENGES Dr. HARSHILAL P. AKHANTHAKAR Prof(Dr.) HASEKH S. PATEL , Prof. PRADHANAM PATIL	29
6	THE STUDY OF MARKET BASED MIND RATE Dr. SOEL GAFTAN BOY CHINDHURY	37
7	A STUDY TO ASSESS THE AWARENESS AND KNOWLEDGE QUOTIENT OF THE INVESTORS WITH REGARDS TO COMMODITY MARKET OF INDIA Dr. SATINDER KALN	44
8	SUGGESTIONS FOR IMPROVING DISCLOSURE PRACTICES OF BANKS Dr. SUNITA GUPTA	51
9	CORPORATE GOVERNANCE DISCLOSURES IN ANNUAL REPORTS OF BANKS Dr. SUNITA GUPTA	65
10	INVESTORS TRADING BEHAVIOR TOWARDS COMMODITY MARKET Dr. P. VENKATANI, MR. K. MURUGAN, DR. MURSHINAMURTHI, DR. C. H. NENTILNATHAN	71
11	AGRICHEMICAL STOCK FORECASTING: AN EMPIRICAL APPROACH ON THE BASIS OF PRE AND POST BUDGET ANNOUNCEMENT FOR 2020-21 JAYESH BHATNAGAR, DR. SIVAGAMI, SUDHAKAR, G. N. SIVAKAN SURESH	79

12	A STUDY ON GROWTH PATTERNS OF MOBILE BANKING IN INDIA M. SUDHAKAR	93
13	BEHAVIORAL FINANCE MURUGUMURUGESAN	96
14	EMERGING TRENDS IN BANKING SECTOR MR. MANJOT KALR, MS. JEMANSHI	99
15	GROWTH OF DERIVATIVES MARKET: A STUDY IN INDIA PALLAVI SHARMA	106
16	A JOURNEY OF BANKING SCHEME OF INDIAN GOVERNMENT: FROM TRADITIONAL TO ELECTRONIC BANKING PROF. PRADHANAM P. PATIL , PROF. DR. HASEKH S. PATEL, DR. TUSHAR SAVALK	125
17	ROLE OF FINANCIAL INSTITUTIONS IN REALIZATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS RAMESHWARI VARMA	132
18	INDIAN BANKING CRISIS IS IMPEDING ECONOMIC GROWTH RAVI KUMAR ALARIA, Dr. DEVA RAM	142
19	THE IMPACT OF BANK INNOVATION ON TOTAL INCOME OF COMMERCIAL BANKS IN CAMBODIA CHRISTOPHER NORTH	152

INDIAN BANKING CRISIS IS IMPEDING ECONOMIC GROWTH

Ravi Kumar Alaria
Research Scholar,
Economics Department, MLSU, Udaipur

Dr. Deva Ram
Associate Professor,
Dr Bhimrao Ambedkar Government College, Nimbahera

ABSTRACT

Banking crisis or NPAs crisis in Indian banks was one of the main reasons for economic slowdown. There are two lending sectors of banks in India i.e., Priority and Non-Priority, where priority sector includes small and micro enterprises, agriculture, education, social infrastructure etc. It's difficult to get credit in this sector. On the other hand, non-priority sector attracts all the financial institutions every time; they are always ready to lend credit. This paper attempts to put forward a concise and comprehensive analysis of priority and non-priority sectors, non-performing assets (NPAs) to total non-performing assets and examine the impact of these two sectors NPAs on total NPAs after global financial crisis 2008. Also try to analyse the impact of recapitalisation on total number of NPAs before COVID-19. The aim is to check whether infusion of fresh capital in public sector banks by government can resolve the problem of NPAs which ultimately helps in improving numbers of GDP.

Key words: Public sector banks (PSB), Priority sector, Non-Priority sector and Non-Performing assets (NPAs).

INTRODUCTION

In any economy, banking system plays very important role for countries growth and development. NPA mean if a borrower doesn't repay his/her debts at their respective due dates because of inability or unwillingness, such debt shows an incorrect picture in the yearend financial statements of banks. Functioning of banking system is direct and positively related to the economy's performance therefore NPAs are a serious threat to banks. A contrasting notion as we all know is NPAs are also life time a friend of bank till the loans and credit system continues.

Public sector banks are the type of banks where a majority stake is held by government. In India, government has control over policies and owns majority share (58 percent) in public sector banks but still NPAs are rising over the period of time in this sector.

Chart: - 1, NPAs of public and private sector banks



DATA SOURCE: RBI; STATISTICAL TABLES

Above chart depicts the data of last 5 years where the total NPAs of private sector banks are nearly about 11 percent of total NPAs, whereas NPAs of public sector banks are about 89 percent of total NPAs. This reflects the ineffectiveness of public sector banks in dealing with NPAs. As we can see NPAs of public sector banks are increasing with faster rate. The measures used by government were ineffective in decreasing the level of NPAs.

In India, NPAs are a solemn risk to both banking sector and economy. Higher NPAs acts as a catalyst for economic growth slowdown, thereby reducing the loan lending power of banks. To overcome this, government recapitalise in public sector banks.

Public sector bank recapitalisation means injection of fresh capital majorly by government and rest through market. This policy was started with an aim to financially strengthen the public sector banks (since government is the majority holder of PSBs shares) and resolution to the problems of bad debts as the rising NPAs which led to erosion of capital. To meet higher capital advance requirements and to accelerate the pace of economic activity has emerged as the highest priority.

But this is probably not a correct remedy for the solution of NPAs.

Indian economy faced major NPAs in priority sector before 2012 but recent trends shows majority of gross NPAs made in non-priority sector.

LITERATURE REVIEW

Mathur, K. B. L. (2002) investigations showed that there is the burden of recapitalisation during the time period 1990-2004 doesn't come out to be as huge as is made out. According to him the real burden on budget was lack of consideration of some other related flows like dividend amounts.

Uppal, R. K. (2009) founded that lending to priority sector creates many problems to Indian banks like transition cost, high NPAs and low profitability. These issues are very serious and it required finding out the solutions, otherwise banking growth of India will cessation.

Rajan, R., & Dhal, S. C. (2003) study shows the recovery rate to total number of NPAs. And they founded that writing off defective loans and bad loans are high in priority sector lending.

Chaudhary, K., & Sharma, M. (2011) studied the relationship between public sector banks and private sector banks NPAs. They concluded that NPAs of public sector banks are higher than private because priority sector lending in public sector banks is higher than private sector.

Selvarajan, B., & Vadivalagan, G. (2013) study shows in dept analysis about the participation of lending activities in public sector banks in priority sector. It showed lending in priority sector by Indian bank grows faster than public sector banks. Performance of Indian banks was better in managing the problem of NPAs than other public sector banks

OBJECTIVES

1. To study and analyse the pattern of NPAs in priority and non-priority sector.
2. To study the trends in recovery and write off rate
3. Measures used by government